श्री उत्तम भाई पटेल : जो टूल्स दिए जाते है वह मैने बता दिया है । जो जिले माननीय सदस्य ने बताए है वह है 1992-93 में कच्छ और पंचमाल, 1993-94 में जामनगर, बनासकांठा, अमरेली और अहमदाबाद तथा 1994-95 में 8 जिले पसन्द किए जाएंगे लेकिन चुनने की स्कीम अभी राज्य सरकार ने भेजी नहीं है ।

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : दूसरा मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया ।...

उपसभापति : आपने क्या पूछा ?

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : मैंने यह पूछा कि उन्होंने खुद ही जवाब दिया है–

"This scheme enables the artisans to enhance the quality of products."

तो जो किट, टूल्स वह देते है उनसे प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसे टूल्स दिए है ?

उपसभापति : आप कौनसे औज़ार देते है जिनसे उनका उत्पादन बढ़ता है ?

श्री उत्तम भाई पटेल : यह मैंने लिखित उत्तर में दे दिया है ।...

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : स्टेटमेंट में कुछ नहीं है ।...

उपसभापति : अच्छा आप पता लगा लीजिएगा मालूम कर लीजिएगा ।

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, मशीनीकरण के कारण ग्रामीण कारीगर बेकार होते जा रहे है और इनकी हालत ज्यादा चिन्ताजनक है । ग्रामीण कारीगरों के ऊपर, ऐसा लगता है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है जिससे उनकी हालत दिन पर दिन चिन्ताजनक होती जा रही है । मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि अब तक पूरे देश में केवल 162 जिलों को कवर किया गया है । इनमें से भी बुनकरों, दर्जियों, कसीदाकारों को वंचित कर दिया गया है, इनको कोई सहायता नहीं दी गई है जबकि ये भी ग्रामीण कारीगर है । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जो जिले है उनको क्यों वंचित कर दिया गया है जहां यह सुविधा और सहायता देनी चाहिए थी ।... इसीसे संबंधित पूरक प्रश्न मैं...

उपसभापति : एक ही प्रश्न पूछिए, एक का जवाब आ जाए ।...

श्री ईश दत्त यादव : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में यह...

उपसभापति : यह उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, इसलिए मत पूछिए ।...

श्री ईश दत्त यादव : पूरे देश का सवाल है, पूरे देश के सभी जिलों को कब तक कवर कर लेंगे, यही उत्तर दे दें ।...

THE DEPUTY CHAIRMAN : The original question is about Gujarat and let the Minister answer. आप मंत्री जी यह बताइए कि आपने खाली 162 डिस्ट्रिक्ट्स किए है, बाकी जिलों को कब तक करेंगे ?

श्री उत्तम भाई पटेल : हमारा यह लक्ष्य है, बिलकुल कवर करेंगे और इसलिए हम सबको यथासमय कवर कर लेंगे ....

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Madam, the hon. Prime Minister has been taking special care to augment the Budgetary allocation for Rural Development as, I understand, it was more than 60 per cent in the last year, and this year also, the Budgetary allocation for Rural Development has been augmented to a great extent. It has been my demand and the demand of many of the women activists that 50 per cent of the Budgetary allocation for Rural Development should be earmarked for the works, projects and schemes beneficial to women. I would like to put a very special question to the hon. Minister regarding the rural artisan scheme. How many women have been benefitted through this rural artisan scheme? I would like to know the details of the women artisans being helped through this scheme.

उपसभापति : महिलाओं के विषय में चूंकि गुजरात से संबंधित सवाल है, उसमें बता दीजिए कि गुजरात में कितने जिलों को दिया गया हैं ।

श्री उत्तम भाई पटेल : ऐसा कोई मतभेद नहीं है । नियमों से जो कारीगरों को देना है वह कैटेगरी के मुताबिक महिलाओं के लिए भी दिया जाता है !

उपसभापति : आप उनका सजेशन मान लीजिए और महिलाओं को भी दे दीजिएगा ।

Better performance of industrial sector

*343. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE :†
SHRI V. NARAYANASAMY :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that industrial sector in the country is going to perform well because of the liberalised policy adopted by Government in giving thrust to the sick infrastructure industries;

†The question was actually asked in the floor of the House by Shri Bishambhar Nath Pande.

(b) if so, what is the target fixed in the industrial sector by Government for the year 1994-95; and

(c) by when the said target is likely to be achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) According to the Index of Industrial Production, the industrial production has shown a rising trend during 1993-94. The latest monthly index for December, 1993, shows an increase of 6.7% in overall industrial production. The overall rate of growth during April—December 1993 was 2.4% as compared with 1.9% during 1992-93.

(b) and (c) Targets for overall industrial rates of growth are not fixed by the Government on an annual basis.

श्री विशम्भर नाथ पांडे : आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां की इंडस्ट्रीज जो 100 वर्ष से ज्यादा से कायम है उनमें मेनली टेक्सटाइल और जूट की है और बाद में उसमें शुगर इंडस्ट्री भी शामिल हो गई और इनकी सारी मशीने आब्सोलीट हो गई और इधर आजादी के बाद नये इंडस्ट्रीज के सेक्टर आ गये है तो सेक्टरवाइज इन्होंने कितनी उन्नति की है और कितना पूंजी निवेश हम 94-95 में लगाने जा रहे हैं ? और क्या कोई नई इंडस्ट्री हम इस बीच में कायम करेंगे ? जिन लोगों ने आसोलीट मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया और उनको माडर्नाइज नहीं किया तो क्या हम फिर उन खत्म हुई इंडस्ट्रीज में पैसा लगायेंगे ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं की पूंजी निवेश में कितना देशी और कितना विदेशी होने की आशा है और किस तरह से उनका डिसबर्सल होगा ? इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि सरकार इस बात से मूलतः अवगत है कि सौ साल पहले हमारे बहुत से कारखानों की स्थापना हुई थी और उनमें तभी से मशीनें लगी हुई है वे आब्सोलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। आज के जमाने में, आज के वैज्ञानिक युग में जहां इतनी तरक्की का माहौल है वहां वे प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पा रही है। इसीलिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। नई औद्योगिक नीति इस वजह से बनाई गई है ताकि हम भी ग्लोबल कम्पीटीशन में आ सकें और जो आब्सोलीट और पुरानी मशीनें है उनको रिप्लेस किया जा सके। इसकी जरूरत है और सरकार ने इस बात को महसूस किया है। इसी उद्देश्य से सभी पब्लिक सेक्टर युनिट्स को माडर्नाइज करने की बात की जा रही है। ज्वायंट वैन्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी पर काफी जोर दिया जा रहा है। आपनें देखा भी होगा कि इन्वेस्टमेंट मार्ट का सम्मेलन पीछे आयोजित किया गया। वह भी इसी उद्देश्य से किया गया ताकि हम केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही न देखे बल्कि ट्रांसफर आफ टेक्नोलोजी कैसे हो इसके ऊपर भी हम जोर दे रहे है। इसका मकसद यह है कि हम यहां जो विदेशी टेक्नोलोजी है उसका उपयोग कैसे हो इसको देखे। केपिटल गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाया गया है ताकि सस्ती कीमत पर यह उपलब्ध हो सके। स्टील पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। बजट में प्रावधान किया गया है कि प्रोजेक्ट इम्पोर्ट के साथ-साथ केपिटल गुड्स में कस्टम ड्यूटी की कटौती के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज के माडर्नाइजेशन पर खर्च में कुछ कमी हो ताकि इसका उपयोग कर सकें। दूसरा इन्होंने फारेन इन्वेस्टमेंट की बात कही। फारेन इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव काफी आ रहे हैं। 1991 में 530 करोड़ के प्रस्ताव आये हैं, 1992 में 3800 करोड़ के प्रस्ताव आये है और 1993 में 9000 करोड़ के प्रस्ताव आये है।

श्री विशम्भर नाथ पांडे : माननीया, मेरा सेकंड सप्लीमेंटरी यह है कि आजादी के बाद हमारी यह घोषित नीति थी कि जिन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज नहीं है, उन क्षेत्रों में भी हमें इंडस्ट्री कायम करनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता था कि क्या ऐसे क्षेत्र निश्चित किये गये है ? मैं अच्छी तरह से जानता हुं कि उड़ीसा, जहां इतनी ज्यादा खनिज सम्पदा है, लेकिन वहां इंडस्ट्री नहीं है। अगर वहां इंडस्ट्री लग जाय तो उड़ीसा जैसा गरीब और पिछड़ा हुआ प्रदेश हिन्दुस्तान के बड़े से बडे औद्योगिक प्रदेशों में हो सकता है। तो अब जो नयी इंडस्ट्रीज आ रही है या आप जो नया पुंजी निवेश लगाने जा रहे है, उसमें ऐसे प्रदेशों का, ऐसे राज्यों का जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, उनका ध्यान रखेंगे या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, सरकार ध्यान जरूर रखेंगी। लेकिन जहां तक नये उद्योग लगाने का प्रश्न उठता है, नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार बार-बार कहती है कि हम परमोटर के रूप में काम करेंगे, हम फैसिलिटेटर्स के रूप में सुविधा प्रदान करेंगे और उनकी हर प्रकार से हम सहायता करेंगे। सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह बहुत बड़ी राशि लगाकर उद्योगों की स्थापना करे। ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना सरकार द्वारा की गयी है जो हमारी अष्टम योजना के लिये भी है। देश में बहुत सारे जिलों

में ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना की गयी है, जहां इन्फास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिये मुहैया कराया जायेगा। ग्रोथ सेंटर की अनुशंसा राज्य सरकारें करती है और उसके मुताबिक भारत सरकार स्वीकृति देती है। उड़ीसा की बात उन्होंने कही है। तो उड़ीसा के लिए जो ग्रोथ सेंटर्स है, हमारे पास उनके नाम उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रश्न से यह नहीं उठता है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने जगहों के जो नाम पूछे है कि कहां स्वीकृत हुए है और उनमें कितना काम हुआ है, इसकी सूची मैं उनको भेज दूंगी।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, the question is very specific that after the introduction of the liberalised economic policy, whether there is any boost to the thrust given by the Government for sick infrastructure industries. But in the reply given by the hon. Minister, that part is missing. The thrust is for the sick infrastructure industries. Steel, Coal, Telecommunications and Power are the infrastructure industries. And because of obsolete technology and old machinery, these industries were suffering. And because of new economic policy adopted by the Government and the concessions given by the Government by way of the Budget, these industries are now in a revival stage. Therefore, I wanted to know from the hon. Minister as to what the growth is in that particular sector. But the hon. Minister gave a general reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now you ask a specific question.

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, the reply has not come to the specific question from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will get the answer for a specific question.

SHRI V. NARAYANASAMY : No, Madam. I need your protection because when we put a specific question...

AN HON. MEMBER : You don't need anybody's protection.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It should be left to me to decide who needs protection in this House. Okey, let me get that reply. The answer was not in the written reply.

SHRI V. NARAYANASAMY : Therefore, I may be permitted further Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not further. I have got lots of names...

SHRI V. NARAYANASAMY : I will complete this question and let her answer fully.

Madam, the Industry Department brought out a policy of getting old machinery from abroad for modernising the existing industries. Earlier, the general limit for this machinery has been fixed at seven years. If it is of beyond seven years, it will not be allowed to be imported is at into the country for the infrastructure industries and other industries. Now that clause has been removed. And the situation is that all the old technologies and the old machineries available in the developed countries will be dumped in this country. I would, therefore, like to know from the hon. Minister as to what are the reasons for removing that clause because of which you are only getting old machinery when you have to compete in the international field with the globalisation of our economy. I would like to know the reasons for removing that clause.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is a very important question and I would like the Minister to elaborate.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, पहले तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि इनका जो प्रश्न है वह सिक इनफास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का है। लेकिन पहले मैंने सोचा कि इनफास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो है वह अधिकांश सिक नहीं है। मैंने पहले तो यह समझा कि यह सिक नहीं होगा, यह सिक्स होगा अर्थात् छः इनफास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है... (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY : The Minister should know how many coal-mines have been closed, how many cement industries have been closed, how many power corporations are in the red. There are sick units even in the infrastructure industry which the hon. Minister should know.

THE DEPUTY CHAIRMAN : you know, Mr. Narayanasamy is well-informed. Let the Minister also give further information.

SHRIMATI KRISHNA SAHI : I know the hon. Member is very well-informed and he knows many things. But what I thought was that it is not 'sick' but 'six' which he was referring to. वही सोचा था, हो सकता है मैंने गलत सोचा हो।

SHRI V. NARAYANASAMY : It is printed as 'sick' and not 'six'.

श्रीमती कृष्णा साही : लेकिन मेरा कहना यह है कि... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN : It was good enough that it was not understood as 'Sikhs' who are Members of this House.

SHRI V. NARAYANASAMY : How can the hon. Minister presume?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : इन्होंने एच० नहीं लगा दिया नहीं तो सब हो जाता (**व्यवधान**)

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, मैं अब प्रश्न के उत्तर पर आ रही हूं। मैं जवाब दे रही हूं। मैं कहना चाह रही थी कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कोयला, स्टील, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्टस, क्रुड पेट्रोलियम और सीमेंट यह सब महत्वपूर्ण इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत आती है। जो ट्रेंड है इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का वह एव्रेज इनक्रीज इन प्रोडक्शन दिखाया है और उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। 1993-94 में 5.3 परसेंट, 1992-93 में 3 परसेंट वृद्धि है। यह पोजिटिव ग्रोथ है। दूसरी बात है मेनुफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज की। उसमें 17 ग्रुप्स है जिनमें 12 groups have shown positive rate of growth from April to December 1993 and then the focus which concerns my department is the manufacturing industries. जो उसी सेक्टर में आता है। मेरा कहना यह है कि उसमें इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो है उसमें पोजिटिव ग्रोथ है। मेनफेक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज में भी पोजिटिव ग्रोथ है। जो यूजर बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रुप्स है उसमें भी पोजिटिव ग्रोथ है। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहती हूं कि 1991-92 में 0.0 था, 1992-93 में 1.9 हुआ और 1993-94 में 6.7 हुआ। मैंने यह नहीं कहा है कि बहुत बड़ा जम्प हो गया है लेकिन यह हमने कहा है कि हमारा इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मॉडरेट है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए जो सही है वह मैंने बताया है। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न था वह भी मैं कहना चाह रही हूं। इन्होंने कुछ क्लाज चेंज करने के बारे में कहा। यह इंडस्ट्रीयलिस्ट जो है यह पहले they are expected to know the relevant technology. कौन पुरानी टेक्नोलोजी लेना चाहेगा, कैसे करना चाहेगा, यह हमारे इंडस्ट्रीयलिस्ट पर निर्भर करेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question was that you have changed the clause by which the limit was seven years in regard to import of machinery from abroad. Having removed it ... *(Interruptions)*

श्री दिग्विजय सिंह : हिंदी में बोला जाये इतना ही कह रहा हूं।

उपसभापति : वह अंग्रेजी का क्लाज है।

श्री शंकर दयाल सिंह : यह अजीब बात है कि मंत्री जी को आपको समझाना पड़ रहा है।

उपसभापति : नहीं, नहीं, समझाना नहीं पड़ रहा है... **(व्यवधान)** प्लीज, नारायणसामीजी ... **(व्यवधान)** मंत्री जी समझदार है लेकिन अगर 5-6 क्वेश्चन्स एक ही बार में पूछे जाते है तो मैं भी कन्फयूज हो जाती हूं, मंत्री जी भी कन्फ्यूज होती है और आप भी कन्फ्यूज होते हैं। बेहतर यह है कि एक वक्त में एक सवाल पूछे और मंत्री जी उसका सीधा जवाब दें। नारायणसामी जी का सादा सवाल है... (व्यवधान) यह सवाल है कि 7 वर्ष का जो क्लाज था वह आपने निकाला था रेस्ट्रिक्शन तो अब कोई भी पुरानी इंडस्ट्री बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान में आकर डम्प कर देगी उससे हमारा जो कम्पटीशन है बाहर के मुल्कों से वह हो नहीं पायेगा। यह उनका सवाल है। ठीक है, ओ० के०।

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, एक साथ इतने प्रश्न आ जाते है कि कभी कभी ... **(व्यवधान)** मैं बताना चाहती हूं कि जो क्लाज के रिमुवल की बात उन्होंने कही है उस क्लाज के लिए इन्टरप्रेन्योर्स जो हमारे है वे फ्री है, स्वतंत्र है कि कैसे कार्मशियल जजमेंट का उसमें इस्तेमाल करेंगे और पांच साल के लिए residual life of machinery has been retained लेकिन इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो हमारा रीसेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो हमारा ट्रेन्ड है वह बहुत पोजिटिव है और मैं कहना चाहती हूं ... **(व्यवधान)** आप हमारा सुनिये तो। जब क्लाज हटाने से नुक्सान ही नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते है। क्लाज हटाने की जो बात कह रहे है उसका मैंने उत्तर दे दिया है। दूसरा यह भी कह रही हूं कि आसार हमारे अच्छे नजर आ रहे है। हम अच्छी प्रगति की ओर बढ़ रहे है तो हम कैसे जबर्दस्ती इसको मान ले कि हम नीचे की ओर जा रहे है या हमारा इन्वेस्टमेंट... **(व्यवधान)** कम हो रहा है।

MISS SAROJ KHAPARDE : I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the industrial sector has not performed well during the last two years; the growth rate was sluggish. I would also like to know whether the Budget for 1994-95 had given sufficient incentives for giving a thrust to industrial growth. If so, what is the response of the Indian industry to it?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, हमारा ट्रस्ट तो इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की ओर है, प्लान आउट-ले हमारा बढ़ाया गया है, स्पेशल टैरिफ कन्सेशन, फारेन इन्वेस्टमेंट और प्रायवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है और बढ़ाया

गया है। एक तो इन का यह प्रश्न था। दूसरा क्या था।

उपसभापति : इन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट जो हैं वह उनके मुताबिक बढ़ी नहीं है और इस विषय में आप क्या कह रहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : ग्रोथ रेट तो हमारा बढ़ा ही है। मैंने पहले भी उत्तर दे दिया है, अभी भी मैं उत्तर देना चाहती हूं और यही मैं कहना चाहती हूं... (व्यवधान) आप ध्यान से सुनिये मैं बताती हूं। ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा है। मैंनुफैक्चरिंग सेक्टर में 1991-92 में... (व्यवधान)

MISS SAROJ KHAPARDE: I would like to know from the hon. Minister, specifically.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, मैंनुफैक्चरिंग सेक्टर में 1991-92 में हमारा 1.5 बढ़ा है और 1992-93 में हमारा 1.4 बढ़ा है, 1993-94 में अप्रेल से दिसम्बर तक 1.8 बढ़ा है, माइनिंग में 0.1 बढ़ा है.... (व्यवधान) ओबर आल भी मैंने पहले बताया है कि 1992-93 में 1.9 एण्ड 1993-94 में 2.4 बढ़ा है और परफारमेंस में जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसमें भी ओवर आल वृद्धि हुई है। हमने और भी बताया है, पहले भी बताया है कि हमारा जो एवरेज इन्क्रीज है वह 5.3 है और 1992-93 में 3 परसेंट है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: The target was 5 per cent. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीया उपसभापति जी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करती है। केवल आशावादी होने से या शुभ इच्छा रखने से या केवल नीतियों को उदार बना देने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ता नहीं है और जैसे कि मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि 1.9 फीसदी की वृद्धि औद्योगिक उत्पादन में किसी भी स्तर से संतोषजनक नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए जो आवश्यक चीज़ें है जैसे बिजली, सड़कें, परिवहन, संचार के माध्यम, वित्तीय संस्थानों में लोगों का विश्वास या उचित श्रम कानुन इन तमाम चीज़ों में सुधार के लिए, इन तमाम क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय योजना कर रही है ताकि देश में औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक ढंग से बढ़ सके?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सहायता देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है। 1993-94 तथा 94-95 के बजट तथा व्यापार एवं राजकोषीय नीति के क्षेत्र में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

टैरिफ के स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन और सिम्प्लीफिकेशन, इंपोर्ट तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती, स्टैटुटरी लिक्वीडिटी एवं कैश रिजर्व रेस्यो में कटौती की गई। इस कारण इंडस्ट्रियल सैक्टर में अधिक ऋण उपलब्ध हो सकेगा। कर्मशियल एडवांसेज के मिनिमम लैंडिंग रेट्स में कटौती की की गई है। चालू खाते में रुपये की कन्वर्टिबिलिटी की गई है।.... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

श्रीमती कृष्णा साही : इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए केन्द्रीय योजना में आवंटन की गई है और इसके साथ-साथ हमने एस० एस० आई० स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस किए है। प्रोविजंन फॉर इनफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया है। प्रोविजन आफ् कंसेशनल फाइनांस आन् एक्साइज बैनिफिट्स किया है।

marketing support through reservation of items for exclusive production in this sector, reservation of items for purchase from the small-scale units, supply of machinery on hire purchase basis, provision of technical, managerial and economic... *(Interruptions)*...

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARSIMHA RAO): Madam, may I supplement the answer? The hon. lady Member from the other side very rightly asked a question about infrastructure. May I remind the hon. Members that from the word "go", our entire emphasis has been on the creation of new infrastructure? It is well known that we will fall short in power; our telecommunications are none too happy; our roads are not as good as they should be. So, in every department of the infrastructural game, we have been lagging behind. So the question is, if you want to industrialize, how can you do it without infrastructure? So we have gone with the first demand everywhere, that the first preference—our preference—is for infrastructure. Lots of difficulties have been encountered. The Electricity Boards, for instance, in the States are not doing too well and, in any case, power is in the State sector. So, the question of creating coordination between the Central Government clearances and clearances at the State level had to be addressed, which have been addressed quite successfully except in the case of a few States. This is a continuous process. In some States there has been remarkable improvement. In some States they are still lagging behind. So the picture is bound to be mixed for some time to come. So hon. Members would kindly bear with the Government while these efforts are going on. In

fact, I want the hon. Members to help the Government in creating this infrastructure, creating conditions of co-ordination. If we give a grant, at least the grant should be spent for the puposes for which it is given. If clearances are given, the clearances have to be acted upon. So, all this is happening in some States, not happening in some other States. Again I say, it is a mixed picture. So we all are putting our shoulders to the wheel.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Next question.

DR. BIPLAB DAS GUPTA : Madam, this is an important question.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I know, this is an important question.

That is why the Prime Minister has answered it ... *(Interruptions)*

Induction of Missiles into Defence Services

*344. SHRI K.R. MALKANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state when Government propose to introduce various missiles ably developed and successfully tested by us into the Defence Services?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : Surface-to-surface missile PRITHVI and short range, surface-to-air missile TRISHUL are expected to be inducted in the Defence Forces during 1994-95 and 1995-96 respectively. Development work on medium range, surface-to-air missile AKASH and third generation anti-tank missile NAG is expected to be completed during 1995-96 after which both these missiles are to enter the user's trials, production and induction phase.

SHRI K. R. MALKANI : Madam Deputy Chairman, there are very disturbing reports about the fate of the Agni missile. There are reports in very responsible sections of the Press that the Government has decided not to permit any further testing for an indefinite period. It has also been reported that the Defence Research and Development Organisation has asked for a sum of Rs. 50 crores to carry out three more tests and that this amount has been denied to it. It has further been alleged that this decision had been taken at the instance of pressures from abroad. Would the Government come clean on all these issues and tell us where the Agni missile stands?

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : Madam, let me clarify, there is no pressure from abroad. There is no question of that. I do not know what to do when there is no pressure. The other questions do not arise.

This question is only about Trishul and Prithvi. Let us confine the supplementaries to the question and not go far away from it.

SHRI K.R. MALKANI : Madam, my first supplementary has not been answered. Has the sum of Rs. 50 crores been denied or not? This is the point. Has the testing been put off indefinitely or not? These questions have not been answered. ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN : It does not arise because there is no such pressure.

SHRI K. R. MALKANI : That is one part. ... *(Interruptions)*

SHRI P.V. NARSIMHA RAO: Madam, I rose only to allay the kind of fears that have been expressed and the doubts that have been created. Otherwise, the question is confined to Prithvi and Trishul and may be other also... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN : Just a minute. ... *(Interruptions)*

All are missiles. They include Prithvi and others. ... *(Interruptions)*

Let him answer. ... *(Interruptions)*

All right, Agni also. ... *(Interruptions)* Okay, okay.

SHRI P.V. NARSIMHA RAO : The question is concerned with induction of our missiles into the armed forces. Precisely that has been answered.

About the fears, I have allayed the fears.

About things which are not contained in this or are not contained in the answer, I am afraid, no answer is possible in detail here.

उपसभापति : मंत्री जी आपको इसमें कुछ एड करना है ?

SHRI MALLIKARJUN : I have nothing to add to it. ... *(Interruptions)*

THE LEADER OF APPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT) : The word "introduction" is related to introducing the missiles in the army. This question is related to the whole range of missiles... *(Interruptions)*

SHRI K.R. MALKANI : Scentists and technicians of the DRDO have given an excellent account of themselves by developing Agni. How is it that in this situation the leader of this team is being transferred out? Will it not be interpreted in the country and abroad as an effort to kill the programme and to put it in deep freeze?

SHRI P.V. NARSIMHA RAO : I can only deny it absolutely as emphatically as he is raising it. That is all.